[श्री प्रमोद महाजन]

उत्पादन पर किसी प्रकार की लेवी नहीं होती है, कहीं भी कपड़ों की लेवी नहीं है, दवाइयों पर लेवी नहीं है, कोटन [illegible] नहीं है, पुस्तकों पर लेवी नहीं है। किसानों को जिन चीजों की जरूरत हो, आवश्यकता हो उन्हें कहीं से भी लेवी से लाकर किसान को सस्ते में नहीं दिया जाता है लेकिन किसान जिन चीजों का उत्पादन करता है उन पर जबर्दस्ती से लेवी लाद दी जाती है और इसीलिए इस लेवी के सिद्धांत का मैं सिद्धांततः, मूलतः विरोध करता हूं और केन्द्र सरकार से आग्रह-पूर्वक मांग करता हूं कि चावल की लेवी की इस आज्ञा को वे तुरंत वापस लें और यदि अनाज भण्डार में चावल की कमी हो तो बाजार में जाकर बाजार के भाव से किसानों से धान खरीदकर भण्डार की आपूर्ति कर लें, लेकिन किसी भी हालत में लेवी की जबर्दस्ती धान उत्पादक किसानों पर करके उन पर अत्याचार न करें। इस प्रकार अगर अत्याचार होगा तो स्वाभाविक रूप से धान उत्पादक किसानों में व्याप्त असंतोष एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है और इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस प्रकार की जबर्दस्ती की लेवी से किसानों को मुक्त रखें।

Demand for Extending Special Developmental Facilities to the Backward HUl areas of Karnataka

SHRI R. S. NAIK (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to draw the attention of the House, through you, to an important matter. Some of the backward hill areas of the country have been identified as hill areas and are receiving special attention for development of that area since the Fourth Five-Year Plan of the country.

In addition to this, many important policy measures and certain liberalised pattern of central assistance have been extended to hill regions. So hilly people are benefited in getting some type of subsidy as some norms have been relaxed recently. I appreciate the atand taken by the Govern* ment for development and uplift-ment of that hilly region or people.

Sir, my Special Mention here is not about that. My Special Mention is about many hill regions in the country which have been cornered and thereby the people of those areas have been deprived of the normal facilities which have been extended by the Government. They are excluded from facilities like gas concession to the consumers of L.P.G. connections, kerosine concession, other subsidy and so on and so forth.

Un Karnataka, 17 to 18 talukas which lay on the parts of Western Ghat have remained excluded from hill area. Actually, these are all hill areas. But they require the approval of the Planning Commission. In this connection, the State Government has been corresponding with the Planning Commission in order to clear doubts and get the sanction as early as possible.

Sir, in Karnataka, North K. District is my home district and Dandeli has been deprived of this facility and a lot of agitation is going on there in order to get the gas concession. So many social organisations nnd women organisations have started agitation for the inclusion of Haliyal Munda-god in the list of hill areas so that they may get the benefits and concessions given to hill areas. So, my request to the Government is that the identification of hill area needs to be given a second look immediately by the Planning Commission as per the norms prescribed by the Central Government for the identification of lull areas. In Karnataka, 17 to 18 *talukas* have become eligible for inclusion in the Western Ghat Region. So, I urge upon the Government tfoi inclusion of Haliyal Mundagod in North K. District and Sorab and other talukas which come under the Western Ghat go that they get all the facilities. Otherwise, this type of agitation will be started not only in Kar-

nataka but also everywhere in the country where the hill areas have not been recognised properly. So, I request the Government to instruct the Planning Commission to include the *talukas* which have been left out from the list of hilly areas. With these words, I conclude.

Cfrfats in Diamond Cutting: Industry

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रमुख उद्योगों में हीरा तराशने और पालिश करने का एक मुख्य उद्योग है । इसका हमारे आर्थिक विकास में कितना बड़ा योगदान है, यह इसी से पता चलता है कि प्रति वर्ष हमारे देश से 2,400 करोड़ मूल्य के हीरे प्रतिवर्ष निर्यात किये जाते हैं लेकिन इस उद्योग में जो मजदूर लगे हुए हैं, उपसभाध्यक्ष जी, उनके अंदर बहुत असंतोष बढ़ रहा है और उनके असंतोष के कारण इस उद्योग को बड़ी हानि भी हो रही है।

इस उद्योग में केरल के त्रिचूर जिले का बहुत बड़ा हाथ है। उस एक जिले में करीब-करीब एक हजार इकाईयां हैं जो हीरा काटने और पालिश करने के काम में लगी हुई है और करीब-करीब 25 हजार मजदूर उन इकाईयों में काम कर रहे हैं।

लेकिन आज उनमें से सौ इकाइयां या उससे ज्यादा मजदूरों के असंतोष के कारण बंद हो चुकी हैं । इन इकाइयों को प्रतिवर्ष बम्बई और गुजरात के व्यापारियों से प्रतिमास 168 करोड़ रुपये के मूल्य के हीरे कटाई और पालिश करने हेतु प्राप्त होते हैं । इस उद्योग में लगे मजदूर इस बात के लिए आन्दोलन कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी किया जाए, उन्हें ई०एस०आई० की सुविधा दी जाए, प्राविडेंट फंड की सुविधा दी जाए और उन्हें बोनस दिया जाए । मोटे तौर से एक इकाई में न्यूनतम 100 कैरट खुरदरे हीरे पर काम करने के लिए कम से कम 100 मजदूरों की आवश्यकता होती है। एक कैरेट खुरदरे हीरे की कीमत 4500 से 5000 रुपये तक होती है । एक कैरेट हीरे की कटाई और पालिश के बाद कीमत लगभग 7500 रुपये होती है । एक कैरेट हीरे की कटाई और पालिश के लिए बम्बई और गुजरात के व्यापारी 18 से 20 रुपये देते हैं जबकि मजदूरो को करीब 12 रुपये मिलते हैं। हीरों के व्यापारियो का कहना है कि एम०एम०टी० सी० और हिन्दुस्तान डायमंडज कारपोरेशन को चाहिए कि त्रिचूर जिले में अपनी शाखाएं खोलकर यहां कार्यरत 1000 इकाइयों को खुरदरे हीरे उपलब्ध करायें ताकि कटाई और पालिश के काम में लगे लोगों को बम्बई और गुजरात जाकर ये हीरे न प्राप्त करने पड़ें । त्रिचूर के हीरे अन्तर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं । खुरदरे हीरों की नियमित व्यवस्था के बिना इस उद्योग में लगे मजदूरों को नियमित रोजगार तथा मजदूरी प्रदान करना कठिन है । इस कार्य को स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट अथवा केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड एम्प्लायमेंट कारपोरेशन या केरल स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन सुगमता से कर सकती है । त्रिचूर के हीरा व्यापारियों का कहना है कि चूंकि हीरे तराशने और पालिश करने का कार्य गुजरात और बम्बई से प्राप्त होने वाले खुरदरे हीरों पर निर्भर करता है अतः इस उद्योग में लगे मजदूरों को ई०एस०आई० जैसी सुविधाएं देना या प्राविडेंट फंड का लाभ देना संभव नहीं है । 100 इकाइयां मजदूरों के आन्दोलन के कारण बन्द हो चुकी हैं और अन्य दूसरी इकाइयां भी बंद होने वाली हैं । हीरे के व्यापारियों का यह भी कहना है कि यदि उद्योग की सहायता करने हेतु सरकार आयकर और बिक्री कर में समुचित सुधार कर दे तो हीरों का निर्यात 2400 करोड़ से बढ़कर 6000 करोड़ हो सकता है और यह उद्योग 5 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग को बन्द होने से बचाने के लिए खुरदरे हीरों की सप्लाई की व्यवस्था त्रिचूर की इकाइयों को वहीं उपलब्ध करायें, इस उद्योग में